

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 651] No. 651] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2009/वैशाख 3, 1931

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2009/VAISAKHA 3, 1931

# वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2009

का.आ. 1002(अ).—यत: मै. मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. ने मध्य प्रदेश राज्य के ग्राम गंगा मालनपुर, तहसील एवं जिला ग्वालियर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यत: केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनयम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने मध्य प्रदेश राज्य के ग्राम गंगा मालनपुर, तहसील एवं जिला ग्वालियर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं हेतु उक्त अधिनयम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 25 अक्तूबर, 2006 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अत: अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के ग्राम गंगा मालनपुर, तहसील एवं जिला ग्वालियर में निम्नलिखित क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित ब्लॉक संख्या और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :—

तातका			
क्रम. ग्राम का नाम सं.	खसरा संख्या	क्षेत्र फल (हेक्टेयर में)	
(1) (2)	(3)	(4)	
1. गंगा मालनपुर	406/1	1.446	
2.	406/2	1.118	
3.	407/1	2.811	
4.	407/2	2.027	
5.	408	1.588	
6.	412 मिन	2.571	
7.	412 मिन	0.439	
	क्ल	12.000	

[फा. सं. 2/446/2006-एस ई जेड] भारती एस. सिहाग, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2009

S.O. 1002(E).— Whereas M/s. Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Limited, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services sector at Ganga Malanpur Village, Tehsil and District in the Gwalior in the State of Madhya Pradesh;

And whereas the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services sector at the said Ganga Malanpur Village, in the Tehsil and District Gwalior in the State of Madhya Pradesh on 25th day of October, 2006;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the following area at Ganga Malanpur Village, in the Tehsil and District Gwalior in the State of Madhya Pradesh, comprising of the Survey numbers and the area given in the Table below, as a Special Economic Zone, namely:—

1	٦Δ'	Rī	I
_ 1	_	LJK.	-42

SI. No.	Name of Village	Khasra No.	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ganga Malanpur	406/1	1.446
2.	. 5 1	406/2	1.118
3.		407/1	2.811
4.		407/2	2.027
5.		408	1.588
6.		412 min	2.571
7.		412 min	0.439
		Total	12.000

[F. No. 2/446/2006-SEZ] BHARATHI S. SIHAG, Jt. Secy.

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2009

का.आ. 1003(अ),—िवशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 4 के प्रयोजनार्थ में. मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉपोरेशन लि. द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के ग्राम गंगा मालनपुर, तहसील एवं जिला ग्वालियर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं हेतु विकसित विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात :—

- इंदौर विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त —अध्यक्ष, पदेन
- निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, —सदस्य, पदेन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उनका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम न हो
- 3. संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, भोपाल —सदस्य, पदेन
- 4. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिनका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं हो

- 5. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार —सदस्य, पदेन रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिनका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम न हो
- निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, सदस्य, पदेन भारत सरकार
- 7. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले ——सदस्य, पदेन दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम न हो
- मै. मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स —विशेष आमंत्रिती डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. (विकासकर्त्ता) का प्रतिनिध
- विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त की अनुपस्थित में उनका प्रतिनिधित्व वह अधिकारी करेगा जिसका स्तर संयुक्त विकास आयुक्त से कम नहीं होगा ।

[फा. सं. 2/446/2006-एस ई जेड] भारती एस. सिहाग, संयुक्त सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2009

S.O. 1003(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the sector specific Special Economic Zone for the information technology and information technology enabled services Special Economic Zone at Ganga Malanpur Village, in the Tehsil and District Gwalior in the State of Madhya Pradesh developed by M/s. Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Limited for the purposes of Section 4 of the said Act, consisting of the following Members, namely:—

said Act, consisting of the following Member	ers, namely:
1. Development Commissioner – Indore Special Economic Zone	—Chairperson, ex-officio
2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India	—Member, ex-officio
3. Joint Director General of Foreign Trade, Bhopal	Member, ex-officio
4. Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member, ex-officio
5. Commissioner of Income Tax having	—Member,

 Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India

territorial jurisdiction over the Special

Economic Zone or his nominee not

below the rank of Joint Commissioner

—Member ex-officio

ex-officio

–Member, 7. Two officers, not below the rank of ex-officio Joint Secretary, to be nominated by the Government of Madhya Pradesh

8. Representative of M/s. Madhya Pradesh -Special State Electronics Development Corporation Invitee Limited (Developer)

2. In the absence of Development Commissioner of the Special Economic Zone, an officer not below the rank of Joint Development Commissioner will represent him.

[F. No. 2/446/2006-SEZ] BHARATHI S. SIHAG, Jt. Secy.

# अधिसुचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2009

का,आ. 1004 (अ),—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा दिनांक 23 अप्रैल, 2009 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख से मै. मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के ग्राम गंगा मालनपुर, तहसील एवं जिला ग्वालियर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं हेतु विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित विशेष आर्थिक जोन को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कॅंटेनर डिपो माना जाएगा ।

> [फा. सं. 2/446/2006-एस ई जेड] भारती एस. सिहाग, संयुक्त सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2009

S.O. 1004 (E). - In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby appoints the 23rd day of April, 2009 as the date from which the sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services sector at Ganga Malanpur Village, Tehsil and District-Gwalior, in the State of Madhya Pradesh proposed to be developed by M/s. Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Limited shall be deemed to be Inland Container Depot under Section 7 of the Customs Act, 1962.

[F. No. 2/446/2006-SEZ] BHARATHI S. SIHAG, Jt. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2009

का.आ. 1005(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेशक, सॉफ्टवेयर टेक्नॉलोजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नोएडा को निम्नलिखित तालिका में किए गए उल्लेख के अनुसार विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त के रूप में नियक्त करती हैं ---

	तालिका			
<del></del> क्र. सं.	विकासकर्ता का नाम	स्थान	प्रकार	क्षेत्रफल (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै. मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.	तहसील एवं	सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी १, समर्थित सेवाएं	12 एकड़

2. विकास आयुक्त के रूप में कार्यों का निष्पादन करने के लिए निदेशक, सॉफ्टवेयर टेक्नॉलोजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नोएडा को केन्द्र सरकार, वाणिज्य विभाग तथा विशेष आर्थिक जोन अनुमोदन बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करना होगा । वह वाणिज्य विभाग तथा विशेष आर्थिक जोन अनुमोदन बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित आवधिक रिपोर्टे भी भेजेंगे । वह विकास आयुक्त के रूप में की गई सभी कार्यवाहियों के लिए वाणिज्य विभाग के प्रति जवाबदेह होंगे । तथापि, पदधारी की छुट्टी, स्थानांतरण, तैनाती आदि जैसे वैयक्तिक मामले सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अथवा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इण्डिया, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा शासित होंगे । [फा. सं. 2/446/2006-एस ई जेड]

भारती एस. सिहाग, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2009

S.O. 1005(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) the Central Government hereby appoints Director, Software Technology Parks of the India, Noida, to be the Development Commissioner of sector specific Special Economic Zone, as enumerated in the Table below:-

#### TABLE

Sl. No.	Name of the Developer	Location	Type (in	Area hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Limited	Village-Ganga Malanpur, Tehsil and District- Gwalior, Madhya Pradesh	Information Technology and Informatio Technology Enabled Services	12 hec- n tares

2. For discharge of the functions as Development Commissioner, the Director, Software Technology Parks of India, Noida shall abide by the instructions of the Central Government, in the Department of Commerce and the Board of Approval on Special Economic Zones, issued from time to time. He shall also be sending periodic reports, as prescribed by the Department of Commerce and the Board of Approval on Special Economic Zones. He shall be responsible to the Department of Commerce for all the actions taken as Development Commissioner. However, the personal matters like leave, transfer, posting etc. of the incumbent shall be governed by the Department of Information Technology or Software Technology Park of India, as the case may be.

> [F. No. 2/446/2006-SEZ] BHARATHI S. SIHAG, Jt. Secy.